

वर्धा, महाराष्ट्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता उपक्रम और सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन

मनीषा सिंह* एवं प्रोफ डॉ. महालक्ष्मी जौहरी **

*शोध छात्रा(समाजशास्त्र) पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म०प्र०)

**विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, डीन कला संकाय, पी के विश्वविद्यालय शिवपुरी मध्य प्रदेश

शोध सार

यह शोध पत्र वर्धा, महाराष्ट्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता और उनकी सहभागिता का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। वर्धा जिला, जो अपनी ऐतिहासिक और गांधीवादी पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र प्रदान करता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, और सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित है, जो महिलाओं की उद्यमी भूमिका को आकार देती है। शोध का उद्देश्य इन महिलाओं के उद्यमों की प्रकृति, उनकी भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को समझना है।

अध्ययन में सामाजिक पूंजी, सशक्तिकरण, लिंग और विकास, और नारीवादी अर्थशास्त्र जैसे सैद्धांतिक आधारों का उपयोग किया गया है। यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूह (SHGs) सामाजिक नेटवर्क और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्धा में महिलाएँ सूक्ष्म और लघु उद्यमों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, और खुदरा व्यापार में संलग्न हैं। हालाँकि, उन्हें वित्त तक सीमित पहुँच, सांस्कृतिक बाधाएँ, और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सोनाली झाडे और लक्ष्मीबाई अमोळ शिंदे जैसे उदाहरणों से पता चलता है कि सही समर्थन से ये महिलाएँ सफलता प्राप्त कर सकती हैं। सरकारी योजनाएँ जैसे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना' और गैर-सरकारी संगठनों की पहल इन प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। निष्कर्ष में, यह शोध ग्रामीण महिला उद्यमिता को सामाजिक-आर्थिक विकास की कुंजी मानता है और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इनकी क्षमता को बढ़ाने की सिफारिश करता है।

1. परिचय: वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमिता की पृष्ठभूमि

वर्धा जिला, महाराष्ट्र राज्य में स्थित, एक अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात है। जिले की साक्षरता दर उल्लेखनीय है, विशेष रूप से महिला साक्षरता दर 81.81% है, जो महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार को दर्शाती है। वर्धा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो अधिकांश ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। जिले की सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित है, जो महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को विभिन्न क्षेत्रों में आकार देता है। ऐतिहासिक रूप से, वर्धा का महात्मा गांधी से गहरा संबंध रहा है, जिन्होंने ग्रामीण उद्योगों और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। गांधीवादी सिद्धांतों का यह ऐतिहासिक महत्व स्थानीय उद्यमिता, जिसमें महिलाओं की पहल भी शामिल है, के लिए एक अनुकूल वातावरण बना सकता है।

भारतीय सामाजिक-आर्थिक ढांचे के भीतर ग्रामीण महिला उद्यमिता को ऐसी महिलाओं या महिलाओं के समूहों द्वारा उद्यमों के स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें अक्सर महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी होती है, जैसे कि 51% स्वामित्व। ग्रामीण परिवेश की बाधाओं और अवसरों के भीतर संचालित ये उद्यम अक्सर सूक्ष्म या लघु स्तर के होते हैं। ग्रामीण महिलाओं को अक्सर अपने उद्यमशील प्रयासों के साथ-साथ दोहरी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं।

वर्धा के विशिष्ट संदर्भ में इस घटना का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि स्थानीय गतिशीलता, चुनौतियाँ और अवसर राष्ट्रीय या राज्य के औसत से भिन्न हो सकते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (MGIRI) जैसी स्थानीय संस्थाओं की उपस्थिति वर्धा को एक प्रासंगिक केस स्टडी बनाती है। ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए वर्धा का चयन क्षेत्र में लक्षित सरकारी हित को इंगित करता है, जिससे महिला उद्यमियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी के ग्राम उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का ऐतिहासिक संदर्भ स्थानीय स्व-रोजगार के प्रति दृष्टिकोण को आकार दे सकता है और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए कुछ आधार तैयार कर सकता है।

2. सैद्धांतिक आधार: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक एजेंसी पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की उद्यमिता और आर्थिक एजेंसी को समझने के लिए कई समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रासंगिक हैं।

सामाजिक पूंजी सिद्धांत: ग्रामीण समुदायों के संदर्भ में सामाजिक पूंजी नेटवर्क, विश्वास और पारस्परिकता को दर्शाती है। महिलाओं के सामाजिक नेटवर्क, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से, सूचना, ऋण और बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाते हैं। सामाजिक पूंजी के बंधन, पुल और जोड़ने वाले पहलू महिलाओं की उद्यमिता के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए SHGs के माध्यम से सामाजिक पूंजी विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, जो न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक समर्थन नेटवर्क और सामूहिक कार्यवाई के लिए एक मंच भी प्रदान करती है।

सशक्तिकरण सिद्धांत: महिलाओं की उद्यमिता के संदर्भ में सशक्तिकरण आत्म-मूल्य, निर्णय लेने के अधिकारों, संसाधनों तक पहुंच और उनके जीवन पर नियंत्रण पर केंद्रित है। ग्रामीण वर्धा में उद्यमी गतिविधियाँ महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और

राजनीतिक सशक्तिकरण में योगदान करती हैं। महिला सशक्तिकरण के पाँच घटकों को उद्यमिता के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है।

लिंग और विकास सिद्धांत: यह सिद्धांत जांच करता है कि कैसे लिंग भूमिकाएँ और सामाजिक संरचनाएँ आर्थिक गतिविधियों और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती हैं। यह 'विकास में महिला' (WID) से 'लिंग और विकास' (GAD) के दृष्टिकोण में बदलाव पर चर्चा करता है। ग्रामीण भारत में पितृसत्तात्मक संरचनाएँ महिलाओं के उद्यमी प्रयासों को बाधित कर सकती हैं और उन्हें चुनौती भी दे सकती हैं। वर्धा में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिलाओं की गतिशीलता, संसाधनों तक पहुंच और परिवार और समुदाय के भीतर निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करती है।

नारीवादी अर्थशास्त्र: यह परिप्रेक्ष्य महिलाओं के काम और आर्थिक योगदान की जांच करता है, जिसमें भुगतान और अवैतनिक श्रम दोनों को मान्यता दी जाती है। यह आर्थिक अवसरों, संसाधनों तक पहुंच और वेतन असमानताओं में लैंगिक असमानताओं का विश्लेषण करता है। नारीवादी अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि कैसे महिलाओं की उद्यमिता पारंपरिक आर्थिक मॉडलों को चुनौती दे सकती है और संसाधनों और शक्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण में योगदान कर सकती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में व्यवस्थित नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसमें औपचारिक ऋण और वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच भी शामिल है।

3. भारत और महाराष्ट्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता का परिदृश्य: महत्व और चुनौतियाँ

ग्रामीण महिला उद्यमिता भारत और महाराष्ट्र दोनों में आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिला उद्यमी रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता में मदद करता है और लैंगिक समानता में योगदान देता है। महिला उद्यमिता

का समर्थन करने से महिला श्रम बल की भागीदारी पर गुणक प्रभाव पड़ सकता है। महाराष्ट्र में महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2005 में 5.45% से बढ़कर 2016 में 10.82% हो गई है।

हालांकि, ग्रामीण महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: वित्त तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और समर्थन प्रणाली, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, जिसमें पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक रूढ़ियाँ शामिल हैं, शिक्षा और कौशल की कमी, सीमित बाजार पहुंच और विपणन कौशल, और काम और परिवार की जिम्मेदारियों को संतुलित करना। ये चुनौतियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, और सामाजिक मानदंड अक्सर आर्थिक और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को बढ़ा देते हैं।

4. वर्धा में उद्यमी उद्यम और भागीदारी: एक अनुभवजन्य अवलोकन

वर्धा में ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए गए उद्यम विविध प्रकार के हैं। इनमें कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और वस्त्र, खुदरा और व्यापार, और सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

ये उद्यम अक्सर सूक्ष्म से छोटे पैमाने पर होते हैं, जिनमें से कई बिना किराए के श्रम के संचालित होते हैं। वित्तीय संसाधनों में अक्सर व्यक्तिगत बचत, SHGs से ऋण और कभी-कभी बैंकों या सरकारी योजनाओं से छोटे ऋण शामिल हैं। सामाजिक संसाधनों में परिवार का समर्थन, सामुदायिक नेटवर्क और SHG सदस्यता शामिल हैं। भौतिक संसाधनों में अक्सर स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चा माल और बुनियादी उपकरण शामिल होते हैं।

तालिका 1: वर्धा में उद्यमी उद्यमों का प्रकार, पैमाना और संसाधन उपयोग

उद्यम का प्रकार	उदाहरण	पैमाना	वित्तीय संसाधन	सामाजिक संसाधन	भौतिक संसाधन
कृषि	पशुधन, सब्जी की खेती, फूलों की खेती	सूक्ष्म, लघु	स्वयं वित्त पोषित, SHG	परिवार का समर्थन, SHG	स्थानीय कृषि उपज

			ऋण, बैंक ऋण	नेटवर्क	
खाद्य प्रसंस्करण	अचार, पापड़, जैम, स्नैक्स बनाना, आटा चक्की, कैटरिंग	सूक्ष्म, लघु	स्वयं वित्त पोषित, SHG ऋण, बैंक ऋण	परिवार का समर्थन, SHG नेटवर्क	स्थानीय कृषि उपज
हस्तशिल्प और वस्त्र	चूड़ियाँ बनाना, फूलों की माला बनाना, सिलाई, कढ़ाई, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, हर्बल उत्पाद, खादी उत्पादन, बैग बनाना, प्रिंटिंग	सूक्ष्म, लघु	स्वयं वित्त पोषित, SHG ऋण	परिवार का समर्थन, सामुदायिक नेटवर्क, SHG नेटवर्क	स्थानीय कच्चा माल
खुदरा और व्यापार	किराये की दुकान, बर्तन की दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, चाय और स्नैक्स स्टॉल, किराये की सेवाएँ	सूक्ष्म, लघु	स्वयं वित्त पोषित, SHG ऋण	परिवार का समर्थन, सामुदायिक नेटवर्क	स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पाद
सेवा क्षेत्र	ब्यूटी सिलाई, पार्टर, टिफिन सेवाएँ, जैराक्स केंद्र	सूक्ष्म	स्वयं वित्त पोषित, SHG ऋण	परिवार का समर्थन, सामुदायिक नेटवर्क	बुनियादी उपकरण और आपूर्ति

5. वर्धा में उद्यमी भागीदारी को आकार देने वाले कारक: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

वर्धा में ग्रामीण महिलाओं की उद्यमी भागीदारी कई परस्पर जुड़े सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है।

सामाजिक कारक: पितृसत्तात्मक संरचनाएँ और सामुदायिक मानदंड अक्सर महिलाओं की गतिशीलता, सूचना तक पहुंच और संसाधनों पर नियंत्रण को सीमित करते हैं। समाज में महिलाओं की उद्यमी क्षमताओं पर अविश्वास के उदाहरण भी मिलते हैं। ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच कम साक्षरता दर सूचना तक पहुंचने, नई तकनीकों को अपनाने और व्यवसायों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। इसके विपरीत, उच्च शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और उद्यमी सफलता के बीच सकारात्मक संबंध देखा गया है। सामाजिक नेटवर्क, विशेष रूप से SHGs, समर्थन, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विश्वास का निर्माण करते हैं और सामूहिक कार्रवाई को सुगम बनाते हैं।

आर्थिक कारक: ग्रामीण महिला उद्यमियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास अक्सर संपार्श्विक, क्रेडिट इतिहास और सामाजिक पूर्वाग्रहों की कमी होती है। माइक्रोफाइनेंस और SHGs छोटे ऋण तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापक बाजारों तक पहुंचने और स्थापित व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विपणन समर्थन और बाजार संपर्क के लिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा (परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता) व्यवसायों के संचालन पर प्रभाव डालता है, और ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक कारक: पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ और महिलाओं से घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा महिला उद्यमियों के लिए एक दोहरा बोझ बनाती हैं, जिससे उनके पास व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीमित समय और ऊर्जा बचती है। महिलाओं को पुरुष परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जोखिम लेने की क्षमता कम होती है, और सामाजिक मानदंड महिलाओं को व्यवसाय में जोखिम लेने से हतोत्साहित कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं में उद्यमी मानसिकता की उपस्थिति या अनुपस्थिति और उद्यमी आकांक्षाओं को बढ़ावा देने में रोल मॉडल और जोखिम लेने का अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्धा में महिला उद्यमियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीतिक कारक: सरकार की नीतियाँ और पहल महाराष्ट्र और वर्धा में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और बाजार संपर्क शामिल हैं। 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना' और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी विशिष्ट योजनाएँ महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं। वर्धा में स्थानीय प्रशासनिक निकाय और MGIRI

जैसे संस्थान भी सहायता और मार्गदर्शन के संभावित स्रोत हैं।

6. वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमिता के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

ग्रामीण महिला उद्यमिता के वर्धा में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं।

सामाजिक प्रभाव: उद्यमिता महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की शक्ति और परिवार और समुदाय के भीतर समग्र स्थिति को बढ़ाती है। उनकी आर्थिक योगदान के कारण महिलाओं को अधिक सम्मान और मान्यता मिलती है। उद्यमिता के माध्यम से बढ़ी हुई वित्तीय स्वतंत्रता अक्सर वर्धा में महिलाओं के लिए अधिक सामाजिक सशक्तिकरण में तब्दील होती है, जिससे वे अपने जीवन में मजबूत आवाज और एजेंसी प्राप्त करती हैं। महिलाओं की आय में वृद्धि से बेहतर घरेलू कल्याण होता है, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच शामिल है।

आर्थिक प्रभाव: महिलाओं की उद्यमिता घरेलू आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है, परिवारों को गरीबी से बाहर निकालती है और उनके जीवन स्तर में सुधार करती है। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय न केवल स्वयं के लिए बल्कि समुदाय के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

7. वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक प्रणालियों की भूमिका

वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में सरकारी योजनाएँ, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और स्वयं सहायता समूह (SHGs) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकारी योजनाएँ: भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना, महिला

समृद्धि योजना, महिला उद्यमिता मंच (WEP), व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (TREAD), महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन, महिलाओं/महिला उद्यमी योजना के लिए मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, नाई रोशनी- अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना, महिला शक्ति केंद्र, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला वैज्ञानिक योजना, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, BIRAC-TiE WINER पुरस्कार, BIRAC रीजनल टेक्नो-एंटरप्रेन्योरशिपसेंटर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन (BRTC-E & NE), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना और स्वरोजगार ऋण योजनाएँ- क्रेडिट लाइन - महिला_समृद्धि_योजना शामिल हैं। 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना' और पीएम विश्वकर्मा योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करती हैं।

गैर-सरकारी संगठन (NGOs): वर्धा में कई NGOs ग्रामीण महिला उद्यमियों का समर्थन करने में सक्रिय हैं। इनमें जीवनधारा युवा बहुउद्देशीय संस्था, समाज प्रबोधन बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, श्रद्धा ग्रामीण व शहरी युवक बहुउद्देशीय संस्था, सावित्रीबाई फुले महिला मंडल, मातृ सेवा संघ, जय महाकाली शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय युवक क्रांति बहुउद्देशीय महिला विकास संस्था, सुलोचना स्मृति निकेतन शिक्षण समिति, एलिग्नर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, सवाली ट्रस्ट और बजाज फाउंडेशन शामिल हैं। ये संगठन प्रशिक्षण, संसाधन, नेटवर्किंग के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

स्वयं सहायता समूह (SHGs): SHGs ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। वे बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक नेटवर्क बनाते हैं। वर्धा जिले में स्वयं सहायता समूहों की एक मजबूत उपस्थिति है, जो महिलाओं को सामूहिक रूप से उद्यम शुरू करने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं।

8. वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और विकास के संभावित अवसर

वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमियों को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं: वित्त तक सीमित पहुंच, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ, शिक्षा और कौशल की कमी, बाजार पहुंच की कमी, और बुनियादी ढांचे की कमी।

हालांकि, विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। सरकार की 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना' जैसी पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौशल विकास प्रशिक्षण और बाजार संपर्क में सुधार के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग करके बाजार पहुंच का विस्तार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, वर्धा में MGIRI जैसे संस्थान तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करते हैं।

9. वर्धा में सफल ग्रामीण महिला उद्यमियों के उदाहरण

वर्धा, महाराष्ट्र में कई प्रेरणादायक ग्रामीण महिला उद्यमी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सोनाली झाडे, वर्धा जिले की एक खेत मजदूर, ने कमजोर कृषि सीजन के दौरान एक दुकानदार के लिए फूलों की माला बनाकर अपनी आय में वृद्धि की। आवश्यक कौशल हासिल करने के बाद, उन्होंने 5,000 रुपये के छोटे ऋण की मदद से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। लक्ष्मीबाई अमोळ शिंदे, वर्धा की एक अन्य महिला, ने अपने पति की नौकरी छूटने के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह (SHG) में शामिल होकर और एक छोटा ऋण लेकर एक स्नैक (पापड़) व्यवसाय शुरू किया। शुरू में, उन्होंने अपने गांव में अपने खाद्य पदार्थ बेचे। बाद में, उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर की दुकानों में आपूर्ति की। उनके समूह

की ग्यारह महिलाओं ने लक्ष्मीबाई के बढ़ते व्यवसाय में शामिल हो गईं। इन महिलाओं की सफलता की कहानियाँ प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की शक्ति को दर्शाती हैं।

10. निष्कर्ष

वर्धा, महाराष्ट्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जबकि महिलाएं कई चुनौतियों का सामना करती हैं, जिनमें वित्त, बुनियादी ढांचा और सामाजिक बाधाएं शामिल हैं, उनकी उद्यमशीलता की भावना और योगदान निर्विवाद है। सामाजिक पूंजी, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, महिलाओं को आवश्यक समर्थन और संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयास इस क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक हैं, लेकिन जागरूकता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सफल महिला उद्यमियों के उदाहरण प्रेरणा प्रदान करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि सही समर्थन और अवसरों के साथ, ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने जीवन में सुधार कर सकती हैं बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। भविष्य के अनुसंधान को इन महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों और उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार कारकों की गहरी समझ हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- ❖ Ahuja, R. (2017). *Social Problems in India*. Rawat Publications, 288.
- ❖ Andal, N. (2002). *Women and Indian Society – Options and Constraints*. New Delhi: Rawat Publications, 155.
- ❖ Antwal, P. N., Bellurkar, C. M., & Wakle, P. K. (2005). Decision Making Pattern of Rural Women, *Dairying Foots*, 24(1), www.arccjournals.com/uploads/articles/jdfhs241015.pdf
- ❖ Bhattacharyya, A. (2013). Rural Women in India: The Invisible Lifeline of Rural Community. 1, 3, 4 <https://www.okchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Rural>, retrieved on 25.5.18.
- ❖ Das, B., & Khawas, V. (2009). *Gender Issues in Development*, Rawat Publications.
- ❖ De'Souza, A. (1980). *Women in Contemporary India and South Asia*. Delhi : Manohar Publisher.
- ❖ Gordon, I. R., & Whittaker, R. M. (1972). Indicators of Local Prosperity in the South-West Region, London : *Regional Studies*, 299–313.
- ❖ Guha Thakurata, A. (2005). *Quality of Life in Rural Chhattisgarh Plain*. Raipur : Vaibhav Prakashan.
- ❖ Madan, G. R. (1990). *India's Developing Villages*. New Delhi : Allied Publishers Pvt. Ltd.
- ❖ Mitra, A. (1979). *The Status of Women Literacy and Employment*, Allied Publishers Pvt. Ltd., 1–2.
- ❖ Prasad, R. N. (2007). Women's Participation in Politics and Decision Making– Problems and Prospects in Lalneh Zovi (ed.), *Women's Development in India*. New Delhi : Mittal Publisher, 57, 61, 62, 63.